SHORT NOTICE QUESTION

रामगंगा सिंचाई तथा बिजली परियोजना

S. N. Q 24. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रामगंगा परियोजना के लिए जो धनराशि और समय निर्धारित किया गया था उन दोनों में ही पर्याप्त वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए विदेशों से जो करोड़ों रुपये की मशीनें मंगाई गई थी उसमें से बहुत सी उपयोग में हो नहीं आ सकी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना से सम्बद्ध कुछ उच्च अधिकारी घटिया किस्म के पुर्जे स्थानीय निर्माताओं से मिल कर खरीद रहे हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (d). A statement is laid on the Table on the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The project which was estimated to cost Rs. 67.98 crores in 1961 is now expected to cost about Rs. 97 crores. The target date set in 1961 was 1968-69 and this was changed in 1965 to 1972. Now this has been further extended by one year and the present targct date is June, 1973.

(b) No, Sir. There was underutilisation of some machines at one time due to non-arrival of some basic matching equipment.

(c) No such case has come to the notice of Government.

(d) Question does not arise. However, it may be mentioned that there is a detailed procedure for making purchases for this project. Under this procedure the powers of individual officers have been considerably limited and all bulk purchases have to be approved by the Local Purchase Committee comprising Chief Engineer, Director of Construction, Financial Adviser and Superintending Engineer (Procurement).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विवरण में आपने बताया है कि यह परियोजना 1967 तक पूरी होनी थी और अब बढ़ाकर 1973 तक का समय रखा गया है। प्रारम्भिक अनुमानित व्यय को भी 67 करोड़ से बढ़ाकर 97 करोड़ कर दिया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि बिजलीघर बनने के बाद करीब 110 करोड़ रुपय के लगभग व्यय बैठेगा। क्या यह सही है ? यदि यह सही है तो ऐसी स्थिति में जबकि कुल मिला कर आमदनी आपको तीन करोड़ रुपये सालाना से अधिक नहीं होगी, गवर्नमेंट का इतना रुपया फंसाना और उस पर केवल 5 प्रतिशत आमदनी का होना, क्या व्यावहारिक दृष्टि से ये सारी चीजें संगत प्रतीत होती हैं ? जब यह परियोजना बनाई गई थी उस समय आपके मस्तिष्क में क्या ये सारी बातें नहीं थीं ? बाद में जो इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और अनुमानित राशि करीब ड्यौढी बढ़ गई है सौर समय भी ड्यौढ़ा हो गया है, मैं जानना चाहता हूं कि इसके मुख्य रूप से कारण क्या हैं ?

DR. K. L. RAO : The hon. Member has pointed out the increase in the estimates It is true that the estimate has gone up and is going up. But what I wish to submit is that this is an irrigation project, and in the case of an irrigation project, it will be never possible to say what will be the return, whether it will be six per cent or anything like that. Therefore, a direct return by way of revenue, whether it will be Rs. 3 crores or Rs. 4 crores, we cannot say. The amount may vary, and we cannot look forward to increasing any more than what may be possible by way of direct return.

The main thing that has got to be kept in mind is that this an irrigation project which will irrigate about 13 to 17 lakh acres of land and the amount of electricity that is likely to be produced by this project is 200 megawats,

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो विदेशों से कुछ यंत्र मंगाये गये हैं उनके बेकार पड़े होने के सम्बन्ध में आपने कहा है कि कोई इस तरह की विशेष बात नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय स्थिति यह है कि साठ प्रतिशत बुलडोज़र जो करीब दस करोड़ रुपये के हैं, विदेशों से मंगाये गए हैं और वे बेकार पड़े हुए हैं।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वाशिंगटन में जो इंडिया सप्लाई मिशन है उनको जब पुर्जों के सम्बन्ध में लिखा जाता है तो अठारह अठारह महीने तक पुर्जे नहीं आते हैं और इस बीच मशीनें वहां पर बेकार पड़ी रहती हैं। उदाहरण के लिए मैं एक मशीन का नाम लेना चाहता हूँ। स्क्रेपर 1967 से खराब पड़ा हुआ है जबकि आज 1969 का मई महीना प्रारम्भ हो गया है और अब तक भी उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

जहां तक सस्ते पुर्जों की खरीद का सम्बन्ध है, वहां कुछ इस प्रकार के टैक्नीकल अधिकारी है जो सस्ते पुर्जे खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट का लाखों रुपया उस में लग रहा है और जिन से वे पुर्जे खरीदे जा रहें हैं उनके साथ उनका कमिशन बंधा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी योजना में जिसपर एक अरब दस करोड़ रुपया खर्च होना है, इस प्रकार से कुछ अधिकारी मिलकर बीच में सारी परियोजना का अनुचित रूप से लाभ उठायें, क्या यह उचित हैं और क्या इसकी रोकथाम की आपने कोई व्यवस्था नहीं की है ? यदि की है तो वह क्या है ?

पीछे अध्यक्ष महोदय, कालागढ़ परियोजना के ऊपर एक बड़ा गोलीकांड हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस कालागढ़ परियोजना के सम्बन्ध में समय, रुपये और परियोजना आदि में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वहां कुछ राजनीतिक तत्व इस प्रकार के कार्य करने लगे हैं कि आपको समय पर अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही है।

DR. K. L. RAO : The hon. Member has raised a valid question has. One was about the machinery. What I would like to submit about this is that in the case of the Ramganga project, what happened was the machinery was ordered, for example draglines and some dumpers. All the machines were received at the same time there. Unfortunately, the dragline which is one of the most important equipments was damaged in some parts and these parts had to be obtained again from the USA, and that took time. And that is why till the dragline came into operation, the dumpers had to remain idle. That is how there was under utilisation, or some machinery had to remain idle for nearly a few months.

It is true there has been some trouble about spare parts. There was a dock strike in USA and due to many other unfortunate reasons, there was delay. That is why spare parts were not available. I had been there recently and I specially looked into this question of spare parts. Now I find there will be an even flow of spare parts and there will be no difficulty. Therefore, the number of machines lying idle have been reduced considerably.

About inferior spare parts procured locally, the information with my hon. friend is not correct. There are some parts which can be made in India and they are put on the banned list. They cannot be imported. For example, rubber seals is a part which they feel can be manufactured in this country and its import is banned. After all, the spare parts obtained from indigenous sources is only 1 per cent—just worth about Rs. 3 lakhs whereas spare parts imported from outside amount to Rs. 3½ crores. Substitution of some of these parts by local products is really an endeavour which we should encourage. Even so, it is very little.

About the officers, I am afraid I do not have any information. If the hon. member gives any specific name, I can make enquiries. About the strike being political, I do not know. Unfortunately, strikes are there in a large number of projects. Only the other day I had been dealing about Idikki and there was a strike there. I only wish in major projects, strikes are avoided so that the country may progress. As I said, I have no information. But I feel the work is getting on nicely and

there is no reason why there should be any further set-back.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने पूछा था वाशिंगटन में इंडिया सप्लाई मशिन के बारे में उसको कम से कम भारत सरकार इस प्रकार के निर्देश दे कि जिन योजनाओं में अरबों रुपया देश का लगा हुआ है उनके लिए जो स्पेअर पार्ट्स वहां से मंगाये जाते हैं, और जिनके आने में अठारह अठारह महीने लग जाते हैं और इसकी वजह से मशीनें बेकार पड़ी रहती है, उनको जल्दी भेजा जाए।

दूसरे मैंने पूछा था कि पीछे जब वहां गोलीकांड हुआ था उस में भी क्या किसी राजनीतिक तत्व का हाथ था और यदि था तो क्या वह राजनीतिक तत्व वहां है या नहीं है या उस में कोई सुधार हुआ है। इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

DR. K. L. RAO : We have asked the India Supply Mission to expedite it. Now everything has been straightened and there is even flow of work. About the firing, I cannot add to what I have said, At the moment it is completely peaceful and there is no reason why there should be any trouble hereafter.

SHRI RANGA : From what he himself has said, there seems to be something very seriously wrong regarding the delay, higher expenditure, spare parts and also the negotiations with outsiders for supplying heavy machinery. May I ask him to give us an assurance that between now and the next session, he himself would go there or if he cannot find sufficient time, he would depute some very high official to pay some attention to this? Preferably he himself should go study the matter personally, satisfy himself about the remedial measures that are to be taken and then submit a report to this House.

DR. K. L. RAO : It is a very good suggestion. In fact, I had been there only last week for two days and I looked into it. I can assure the House that the work will go along very quickly. It is one of our very important projects and we are trying to see that the work is accelerated. It is very likely that we would be getting water about six months earlier.

श्री महाराज सिंह भारती : जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से मन्त्री जी ने उन सभी बातों को इन्कार किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी बांध का जस्टेशन पीरिअड दस साल तक होता है। चालू होने के बाद से, लेकिन यह बांध जिस दिन चालू होगा उसी दिन पूरा यूटिलाइजेशन इसका होने लग जाएगा क्योंकि इसका सारा पानी उस नहर में जाएगा जो पहले से चल रही है, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या कारण है कि रूस और अमरीका में जितना समय बांध लेता है उससे दुगना समय तो आप प्रेसक्राइब करते हैं और जितना प्रेसक्राइब करते हैं, उससे दुगने समय में आपका बांध बनता है, इस वास्ते सवाल में जो बातें उठाई गई हैं अगर वे नहीं हैं तो देर होने के फिर कौन से कारण है ?

DR. K. L. RAO : I accept that in respect of Ramganga there has been some delay. This should not have taken more than seven years. Unfortunately it has taken more time. I am myself very unhappy about the situation. All that I can say now is that now we have placed the project in a very good sound condition and we expect the project will be completed in the next three to four years.

श्री राम चरण : जब किसी प्राजेक्ट का आरिजिनल एस्टीमेट बनाया जाता है, तब इस बात को दृष्टि में रखा जाता है कि उसके लिए जो मशीनरी इम्पोर्ट या परचेज़ की जानी हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसके अनुसार कितनी रेक्वायरमेंट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्राजेक्ट के सम्बन्ध में इस बात को मद्देनजर रखा गया कि जो अर्थमूविंग मशीनरी और बुलडोज़र आदि परचेज़ किए गये हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, ताकि काम में विलम्ब न हो। क्या विभाग में कोई अफ़सर है, जो यह चैक करे कि अमुक मशीनरी की कैपेसिटी इतनी है और उससे इतने समय में काम

हो सकेगा ; अगर नहीं है, तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी, जिससे भविष्य में आवश्यकता से अधिक मशीनरी आदि खरीद कर धन का मिसयूज न हो सके ?

DR. K. L RAO : About the machinery we have no trouble. We have always been trying to plan out the machinery expenditure, the machinery that has to be purchased and so on. The increase in the cost of the project is due to the fact that there has been devaluation and also because the height of the dam has been increased by 110 feet. The scope has also been increased because area proposed for irrigation has been increased from 13 lakh acres to 17 lakh acres which means an excess of 4 lakh acres. It is this that has increased the cost from Rs. 67 crores to Rs. 97 crores.

श्री राम चरण : मेरा प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि क्या इस बात का कोई एस्टीमेट बनाया गया है कि जितनी मशीनरी परचेज की गई है, उस की कैपेसिटी कितनी है ।

DR. K. L. RAO : In respect of the machinery there has been no trouble. Everything has been ordered very correctly and the machinery there is working very satisfactorily.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह तथ्य है कि सरकार जितने बाँध बाँधती है, वह पहले उस का एस्टीमेट बनाती है कि उस पर इतनी पूंजी लगेगी और वह योजना इतने दिनों में पूरी हो जायेगी, परन्तु विलम्ब के कारण उस पर पैसा भी ज्यादा लगता हैं और योजना भी समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है ? इस योजना के सम्बन्ध में जो बिलम्ब हुआ, उस का प्रमुख कारण क्या है और उसके लिए कौन दोषी है ? क्या मन्त्री महोदय इस बारे में जांच करेंगे कि इस विलम्ब के कारण क्या हैं और उसके लिए कौन व्यक्ति दोषी हैं और क्या वह दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

DR. K. L. RAO : I agree with the hon. Member. As I have already said, in the case of this project there has been unfortunate delay which I myself greatly regret. Unfortunately, these are projects under the State Governments. Any how I will make enquiries into this and find out whether any person is responsible for the delay.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Banks not Permitted by Reserve Bank of India to Advance Large Amounts of Loans

*1624. SHRI ONKAR SINGH :
SHRI J. B. SINGH :
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that banks have to take permission from the Reserve Bank of India for granting large amounts of loan ;

(b) if so, the names of those banks which were not permitted to grant large amounts of loan by the Reserve Bank during the last one year ; and

(c) the policy of the Reserve Bank in regard to the giving of permission to the banks to grant large loans ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) Subject to the requirement of overall credit poiicy, banks are free to sanction individual loans and advances except that they have to obtain authorisation from the Reserve Bank for certain categories of credit limits of Rs. 1 crore or more to any single party or any limit that would take the total limit enjoyed by such party from the entire banking system to Rs. 1 crore or more.

(b) During the last one year credit authorisation was not granted in one case. It is not the usual practice of the Reserve Bank to disclose to details as it relates to accounts of customers of an individual bank.

(c) Before authorising a limit, the Reserve Bank examines broadly the purpose of the loan to satisfy itself that it is in conformity with the requirement of the Plan